(ख) यह स्वीकृति किस तिथि को दी गई तथा उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां यह परियोजना कार्यान्वित की जानी है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत रेशम उत्पादन का विकास संबंधी कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) परियोजना की लागत 109.98 करोड़ रुपये है।

(ख) दिसम्बर, 1997 में स्वीकृति दी गई थी और इस परियोजना में बिलासपुर, रायगढ़ और सुरगुजा के जिलों में तसर रेशम उत्पादन शामिल है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

(घ) परियोजना में 4000 हैक्टेयर क्षेत्र में तसर का रोपण करने, रोपन बढ़ाने के लिए मुख्य रेशम उत्पादन समितियों का गठन करने, रेशम कीट और रिलींग कोसों का पालन करने, 14 अनाज भण्डारों, 4 पीठ केन्द्रों, 1 पीठ केन्द्र, 30 ग्रामीण स्तर के भण्डारण केन्द्रों, 3 जिला स्तरीय कौसा गोदामों, 1 क्षेत्र स्तरीय अनुसंधान व प्रशिक्षण केन्द्र, 20 रीलरों की प्रत्येक क्षमता वाले 2 रिलींग केन्द्रों तथा परियोजना के क्रियान्वयन और मानीटरिंग के लिए परियोजना कार्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त परियोजना में उसके सफल क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने और परियोजना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसी आशा है कि परियोजना के पूरा होने के बाद प्रतिवर्ष 75 मिलियन टन तसर रेशम और 22.5 मिलियन टन तसर स्पन यार्न का उत्पादन होने के साथ-साथ 10,000 व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

कार्पेट टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट द्वारा कार्य प्रारंभ न किया जाना

1645. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भदोही, उत्तर प्रदेश में "कार्पेट टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट" की स्थापना हेतु वर्ष 1993 में एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इस संस्थान के लिए 10 एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने इस संस्थान के लिए कुछ पदों के सृजन के बारे में वर्ष 1996 में सूचना दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संस्थान द्वारा कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है जबकि इससे संबंधित प्रस्ताव पिछले दो दशकों से विचाराधीन है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने संस्थान के लिए 4.25 एकड़ का प्लाट उपलब्ध कराया है।

(ग) वर्ष 1996 में, उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस संस्थान के लिए पदों के सृजन के एक प्रस्ताव के सम्बंध में सूचित किया था।

(घ) भवन का निर्माण और आधारभूत सुविधाओं आदि प्रदान करने का कार्य पूर्ण हो गया है। इस समय परियोजना संशोधित लागत अंकलन का अनुमोदन और संयंत्र व उपकरणों आदि की खरीद और संस्थान प्रगति पर है तथा परियोजना की समाप्ति को जल्द पूरा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के दस्तकारों के लिए कार्यशाला

1646. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1000 दस्तकारों के लिए एक कार्यशाला (आवासीय) हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार द्वारा 2500 दस्तकारों के लिए कार्यशाला- सहित-आवास हेतु भी एक प्रस्ताव भेजा गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना की 5.35 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण अनुदान राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार से 5.35 करोड़ रुपये की बिवज्ञा के दो प्रस्ताव एक 1000 कारीगरों के लिए वर्कशेड तथा दूसरा 2500 कारीगरों के लिए वर्कशेड-सह-आवास प्राप्त हुए है।